तिब्बत देश

पश्चिमी देशों का आधुनिक भस्मासुर –– चीन

चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को देखकर आजकल भारतीय पौराणिक चरित्र भस्मासुर की याद आती है। यह एक ऐसा राक्षसी चरित्र था जिसने पहले तो भगवान को खुश करके उनसे यह वरदान पा लिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। बाद में उसने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया भर में अपनी विनाशलीला शुरू कर दी। आखिरकार देवताओं पर उसका ऐसा आतंक जमा कि खुद भगवान की सत्ता पर खतरा आ गया।

अमरीका ने भी चीन के साथ दोस्ती जमाकर उसे आज के युग का भस्मासुर बना डाला है। इसे आज के युग का सबसे बड़ा राजनीतिक मज़ाक ही कहा जाएगा कि पहले तो अमरीका और पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए चीन को अपनी पूंजी, अपनी टैक्नोलाजी और अपना बाजार देकर उसे एक आर्थिक शक्ति बनाया। और अब उसी आर्थिक शक्ति के बूते पर चीन ने पश्चिमी देशों की सरकारों से घुटने टिकवाने शुरू कर दिए हैं।

पिछले कुछ साल में शायद ही कोई ऐसा महीना बीता होगा जब चीन सरकार ने तिब्बत या ताइवान के सवाल पर किसी सरकार को न धमकाया हो। चीन की धमकी के आगे अगर श्रीलंका और थाईलैंड जैसे बेचारे देश थर–थर कांपने लगें तो बात समझ में आती है। चीन के डर के मारे इन बौद्ध देशों की सरकारों के हाथ पांव इस कदर फूल जाते हैं कि वे अपने ही देश के बौद्ध संगठनों और नेताओं के निमंत्रण पर वहां आने वाले दुनिया के सर्वोच्च बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा को वीज़ा देने से इनकार कर देती हैं; केन्या जैसी सरकारें एक चीनी घुड़की के आगे घुटने टेक देती हैं और; रूस जैसी वीर बहादुर सरकारें तो बीजिंग की मांग पर दलाई लामा को मंगोलिया जाने से रोकने के लिए उनकी हवाई यात्रा की टिकट ही कैंसिल करा देती हैं।

इन देशों की फटेहाल हालत और चीन के खौफ को देखते हुए इन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, फ्रांस और जापान जैसी सरकारों के मुखिया भी चीन के डर के मारे अपने यहां आने वाले दलाई लामा से हाथ मिलाने से इनकार कर दें तो क्या कहा जाए? और अगर ये नेता अपने जनमत से घबराकर चोरी छिपे या किसी लंगड़े बहाने से दलाई लामा से मिल भी लेते हैं तो भी वे इस सच्चाई को तो नहीं छिपा पाते कि दुनिया भर के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के गीत गाने वाले ये देश चीनी भस्मासुर से कितना डरे हुए हैं।

मई के मध्य में ऐसा ही एक और शर्मनाक उदाहरण बेलजियम सरकार ने पेश किया जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक–सैनिक ताकत बनने का सपना देखने वाले यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। 11 से 14 मई को ब्रसेल्स में होने वाले तिब्बत समर्थक संगठनों के सम्मेलन के उद्घाटन के लिए बेलजियम सरकार दलाई लामा को काफी समय पहले ही वीज़ा जारी कर चुकी थी। वीज़ा देते समय यकीनन बेलजियम सरकार को पता रहा होगा कि दुनिया में चीन नाम का एक ऐसा देश भी है जिसने 1950 वाले दशक से दलाई लामा के शासन वाले देश तिब्बत पर जबरन कब्जा जमाया हुआ है। और यह भी कि चीन के कम्युनिस्ट शासकों को कभी भी यह पसंद नहीं आता कि कोई देश दलाई लामा को अपने यहां आने दे। लेकिन सम्मेलन का समय निकट आते–आते उस के मन पर चीन का खौफ इस कदर बढ़ता गया कि वह दलाई लामा को ब्रसेल्स आने से रोकने के रास्ते ढूंढने लगी।

आखिरकार अपनी लोकतांत्रिक शर्म–हया को ताक पर रखते हुए बेलजियम सरकार ने रास्ता ढूंढ ही निकाला। सम्मेलन से कुछ दिन पहले अमेरिका की यात्रा पर गए दलाई लामा से मिलने के लिए उसने अमेरिका में तैनात अपने राजदूत को भेजा। राजदूत महोदय ने अपनी सारी प्रोफेशनल शालीनता का उपयोग करते हुए दलाई लामा को बताया कि बेलजियम में उनका स्वागत तो है, लेकिन उनकी इस यात्रा के कारण अगले महीने बेलजियन महाराजकुमार की चीन यात्रा में खटास पैदा हो सकती है। एक ओर तो दलाई लामा को राजदूत महोदय ने ढेर सारे शब्दों में यह संदेश दे दिया कि उनका आना मेजबान सरकार के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। पर इसके बाद अपनी सरकार की झेंप मिटाने के लिए यह भी कह दिया कि अगर इसके बावजूद भी आप आना चाहें तो आपका स्वागत है। यकीनन यह प्रस्ताव रखने वाले राजदूत को दलाई लामा के बारे में यह पता रहा होगा कि वह मेजबान सरकारों की पूरी रज़ामंदी के बिना किसी देश की यात्रा पर नहीं जाते। बेलजियम सरकार को पूरा भरोसा था कि दलाई लामा कभी भी ऐसी हालत पैदा नहीं करेंगे जिसमें चीन सरकार को बेलजियम के महाराजकुमार का अपमान करने का बहाना मिले। इस कांड का एक पहलू यह भी है कि महाराजकुमार चीन की राजकीय यात्रा पर नहीं बल्कि बेलजियम के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में जाने वाले थे। इससे पहले 2005 में भी बेलजियम नरेश की प्रस्तावित चीन यात्रा को ध्यान में रखते हुए बेलजियम सरकार ने दलाई लामा को अपने देश की यात्रा पर आने से रोक दिया था।

ब्रसेल्स के तिब्बत सम्मेलन में दुनिया के 50 से ज्यादा देशों से आए तिब्बत समर्थक संगठनों के प्रतिनिधियों को बेलजियम जैसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता प्रेमी देश की सरकार के इस दब्बू व्यवहार से गहरा दुख पहुंचा। उनके दुख का एक और कारण यह भी था कि पिछले 17 साल से चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए यह पहला मौका था जब किसी सरकार ने दलाई लामा को सम्मेलन के उद्घाटन समारोह से दूर रखा। इस सम्मेलन से ठीक पहले वे लोग न्यूज़ीलैंड में यह देख चुके थे कि किस तरह चीनी भस्मासुर से डरे न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने देश की यात्रा पर आए दलाई लामा का स्वागत करने से मना कर दिया था। लेकिन उनके सामने आस्ट्रेलिया का भी उदाहरण था। वहां के प्रधानमंत्री ने पहले तो चीनी दबाव में दलाई लामा से मिलने से मना कर दिया। लेकिन बाद में अपने यहां के जनमत के सामने झुकते हुए उन्होंने यह कहते हुए उनका स्वागत किया कि आस्ट्रेलिया एक आज़ाद देश है और वह खुद तय करेगा कि उसका मेहमान कौन होगा।

बेलजियम सरकार का यह शर्मनाक व्यवहार दुनिया भर में तिब्बत की आजादी के लिए चलने वाले आंदोलन को तो हताश नहीं कर पायेगा। लेकिन इसने पूरी दुनिया के सामने, खासतौर से आजादी और लोकतंत्र का दम भरने वाली पश्चिमी बिरादरी को यह स्पष्ट कर दिया है कि चीन सरकार अपने उपनिवेशवादी इरादों और अंतर्राष्ट्रीय दादागीरी को उसी व्यापार और आर्थिक ताकत के बूते पर चला रही है जो चीन को पश्चिमी देशों ने अपनी पूंजी, अपनी टैक्नोलाजी और अपना बाजार देकर उपलब्ध करायी है।

अगर लोकतंत्र प्रेमी और स्वतंत्रता प्रेमी देश दुनिया को इस चीनी भस्मासुर से बचाना चाहते हैं तो उन्हें मिलकर इस भस्मासुर के विनाश का रास्ता खोजना होगा। वरना अकेले–अकेले उनकी हालत न्यूज़ीलैंड, थाईलैंड, श्रीलंका और रूस जैसी ही होगी। और किसी दिन यही चीन उनके राष्ट्रीय सम्मान और सार्वभौमिकता को भस्म कर देगा।

– विजय क्रान्ति

फोटो : विजय क्रान्ति

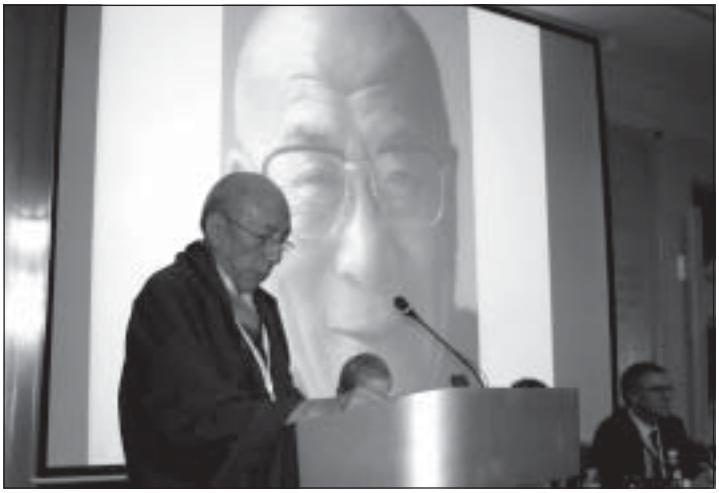

ब्रसेल्स सम्मेलन में प्रो. सामदोंग रिंपोछे : गांधी मार्ग से तिब्बत मुक्ति–साधना

तिब्बत मुक्ति–साधना का अंतर्राष्ट्रीय पर्व

तिब्बत समर्थक संगठनों के ब्रसेल्स सम्मेलन में बीजिंग ओलंपिक पर अंतर्राष्ट्रीय अभियान का फैसला

बेलजियम सरकार के इस धर्मसंकट को देखते हुए दलाई लामा ने अपनी ब्रसेल्स यात्रा रद्द करने का फैसला किया। इससे पहले जून 2005 में भी बेलजियम नरेश अलबर्ट–द्वित्तीय की प्रस्तावित चीन यात्रा को लेकर दलाई लामा को अपनी पहले से निर्धारित बेलजियम यात्रा रद्द करनी पड़ी थी।

तिब्बत समर्थक संगठनों के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 11 से 14 मई के बीच ब्रसेल्स में हुआ। इसमें 56 देशों में सक्रिय 145 तिब्बत समर्थक संगठनों और 36 तिब्बती संगठनों के लगभग 300 सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछले सम्मेलनों की तरह तिब्बत की आजादी के आंदोलन के भावी कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करना था। इसका आयोजन धर्मशाला से चलने वाले तिब्बती निर्वासन प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने जर्मनी की फ्रीडरिश नाउमान श्टिफ्टुंग के सहयोग से किया।

सम्मेलन का एक आकर्षण इसमें चीन के लोकतांत्रिक आंदोलन से जुड़े कई संगठनों की भागीदारी भी था। उनके अलावा तिब्बत की तरह चीन की गुलामी में पिसने वाले सिंकियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

सबसे पहला सम्मेलन 1990 में धर्मशाला में हुआ था। उसके बाद 1996 में बान, 2000 में बर्लिन तथा 2003 में प्राग में इसका आयोजन किया गया था। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन में अब ये सम्मेलन महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुके हैं क्योंकि इन सम्मेलनों में तय की गयी रणनीति के आधार पर ही अधिकांश तिब्बत समर्थक संगठन अपने–अपने देशों में अपने कार्यक्रम तय करते हैं।

अब तक की यह परंपरा रही है कि ऐसे हर सम्मेलन का उद्घाटन दलाई लामा करते रहे हैं। लेकिन इस बार चीन सरकार के दबाव के आगे बेलजियम सरकार के ढुलमुल रवैये ने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिसमें बेलजियम सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए दलाई लामा को अपनी ब्रसेल्स यात्रा रद्द करनी पड़ी। दलाई लामा की प्रस्तावित ब्रसेल्स यात्रा से ठीक पहले उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान वहां बेलजियम के राजदूत ने उन्हें बताया कि चीन सरकार उनकी प्रस्तावित ब्रसेल्स यात्रा पर विरोध कर रही है जिसके कारण अगले महीने एक व्यापारिक प्रतिनिणिधमंडल के साथ चीन की यात्रा पर जाने वाले बेलजियन राजकुमार की यात्रा पर संकट आ सकता है। राजदूत ने उन्हें अपनी सरकर की ओर से अपनी ब्रसेल्स यात्रा पर फिर से विचार करने का आग्रह किया लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दलाई लामा को अपनी सरकार का यह संदेश भी दिया कि अगर वह इसके बावजूद ब्रसेल्स आना चाहें तो उनका उनका स्वागत किया जाएगा। बेलजियम सरकार के इस धर्मसंकट को देखते हुए दलाई लामा ने अपनी ब्रसेल्स यात्रा रद्द करने का फैसला किया। इससे पहले जून 2005 में भी बेलजियम नरेश अलबर्ट–द्वित्तीय की प्रस्तावित चीन यात्रा को लेकर दलाई लामा को अपनी पहले से निर्धारित बेलजियम यात्रा रद्द करनी पड़ी थी।

बेलजियम सरकार के इस कमजोर रवैये पर कई तिब्बत समर्थक और मानवधिकार तथा लोकतंत्र समर्थक संगठनों ने बेलजियम सरकार की निंदा की। बाद में 22 मई को यूरोपीय संसद की बैठक में कई सांसदों ने इस सवाल को उठाया जिस पर संसद के अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि यूरोपीय संसद की ओर से यह मामला बेलजियम सरकार के साथ उठाया जाएगा।

इस मामले में चीन सरकार की बेशर्मी का प्रदर्शन भी शर्मनाक था। बेलजियम में अपनी इस जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बीजिंग में चीन की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने बेलजियम सरकार की तारीफ करते हुए उन सब देशों को चेतावनी दी जिनके यहां दलाई लामा यात्रा पर जाते हैं।

सम्मेलन को भेजे गए अपने संदेश में दलाई लामा ने विश्व जनमत और तिब्बत समर्थकों को याद दिलाया कि तिब्बत का सवाल दलाई लामा का नहीं बल्कि तिब्बत देश और वहां की साठ लाख जनता का सवाल है। उन्होंने चीन के कब्जे में तिब्बती जनता की मुख्य समस्याओं को रेखांकित करते हुए कहा कि तिब्बती

फोटो : विजय क्रान्ति

ब्रसेल्स सम्मेलन में तेंपा सेरिंग, ऑटो लैंब्सडोर्फ, लोडी ग्यारी और अन्य : संघर्ष में साथी

जनता के मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है; तिब्बत के नाजुक पर्यावरण को गंभीर स्तर तक नुकसान पहुंचाया जा रहा है; तिब्बत के भीतर बड़े पैमाने पर चीनी नागरिकों को बसाए जाने से वहां तिब्बती जनता हाशिए पर चली गई है और; इस कारण से तिब्बत की विशिष्ट प्राचीन सांस्कृतिक पहचान तथा धार्मिक भावनाओं पर संकट पैदा हो चुका है।

उन्होंने इस बात पर विशेष चिंता जताई कि चीन सरकार के साथ 2002 से नया संपर्क स्थापित होने के बावजूद हमें वहां सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। उलटे वहां की जनता का दमन और बढ़ गया है जिससे तिब्बत के भीतर और बाहर दोनों जगह हताशा बढ़ती जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस कारण उनकी मध्य–मार्ग नीति की आलोचना बढ़ रही है।

सम्मेलन का उद्घाटन बेलजियम की सीनेट की अध्यक्षा और हुई की मेयर सुश्री अन्ना मेरी लिज़िन ने किया। समारोह में तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री प्रोफेसर सामदोंग रिंपोछे ने अपने संबोधन में तिब्बत–चीन वार्ता के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। तिब्बत समर्थक संगठनों को तिब्बती संघर्ष में उनके योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए आंदोलन के बारे में अपनी सरकार की नीति स्पष्ट की। उन्होंने तिब्बत समर्थक संगठनों के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वासन प्रशासन आपको अपना आंदोलन चलाने के मामले में अपनी नीतियों और रणनीतियों के अनुसार प्रोत्साहित करने, दिशा निर्देश देने और यहां तक कि उसके बारे में आग्रह करने का भी कोई इरादा नहीं रखती है।

चीन सरकार के साथ तिब्बत निर्वासन सरकार की बातचीत के बारे में उनका कहना था कि इस दिशा में चीन सरकार ने कोई उत्साहवर्धक कदम नहीं उठाया है। उनका कहना था कि अगर चीन सरकार क्षेत्रीय स्वायत्तता के बारे में अपने संविधान को भी शब्द और अर्थ दोनो मामलों में ईमानदारी से लागू करती है तो ठीक होगा। इसके साथ यह भी जरूरी है कि हर क्षेत्र में रहने वाले तिब्बती नागरिकों पर एक ही स्वराज्य–सरकार के प्रशासन में रहना होगा। पर उनका कहना था कि चीन सरकार ने अपने सरकारी बयानों और मीडिया के सामने की गई टिप्पणियों में इन दोनो मांगों को अस्वीकार कर दिया है। तिब्बत–चीन वार्ता में पिछले एक साल से आए हुए व्यवधान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि ऐसा इस कारण हो रहा है कि चीन सरकार को इस बारे में अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है।

अपने भाषण में दलाई लामा के विशेष प्रतिनिधि और चीन के साथ बातचीत करने वाले तिब्बती प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री लोडी ग्यारी ने बातचीत की प्रगति का विवरण देते हुए स्वीकार किया कि उनकी ओर से सभी प्रयासों के बावजूद चीन सरकार ने अपनी ओर से कोई प्रभकारी पहल नहीं की है जिससे बातचीत का क्रम थम गया है इस बारे में आशा में कमी आई है।

सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने कई कार्यदलों के माध्यम से तिब्बत आंदोलन से जुड़े विभिन्न विषयों और उनके बारे में अपनी आंदोलन प्राथमिकताओं तथा रणनीति पर विस्तार से विचार किया। विचार के लिए सबसे प्रमुख विषय अगले साल बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों से पहले दुनिया भर में चलाए जाने वाले आंदोलन का स्वरूप रहा। इसके अलावा तिब्बत के भीतर चीन सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन से पैदा हुई परिस्थितियां और वहां चीन सरकार की पर्यावरण विरोधी नीनियां भी तिब्बत समर्थकों की चिंता के मुख्य विषय रहे।

अलग–अलग कार्यदलों द्वारा चुने गए विषयों के आधार पर सम्मेलन के प्रस्ताव तैयार किए गए जिनपर बाद में संयुक्त रूप से विचार किया गया। इन प्रस्तावों में अपनायी गई रणनीति के अनुसार अगले साल बीजिंग ओलंपिक से पहले दुनिया भर में ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से तिब्बत के प्रश्न पर जनमत बनाया जाएगा। इनके अलावा तिब्बत सरकार की बातचीत नीति को समर्थन देने, तिब्बत में मानवधिकारों की बहाली और पर्यावरण के बचाव संबंधी आंदोलन को तेज करने का फैसला किया गया।

– विजय क्रान्ति

अगले साल बीजिंग ओलंपिक से पहले दुनिया भर में ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से तिब्बत के प्रश्न पर जनमत बनाया जाएगा। इनके अलावा तिब्बत सरकार की बातचीत नीति को समर्थन देने, तिब्बत में मानवधिकारों की बहाली और पर्यावरण के बचाव संबंधी आंदोलन को तेज करने का फैसला किया गया।

पंचेन लामा की रिहाई के लिए लंदन में प्रदर्शन : अंतर्राष्ट्रीय चिंता

पंचेन लामा 18 साल के हुए
दुनिया भर में प्रार्थनाएं और प्रदर्शन

चीनी हिरासत से गेदुन छ्योकि नीमा की रिहाई के लिए विश्व समुदाय में बढ़ता दबाव

11वें पंचेन लामा, गेदुन छ्योकि नीमा इस अप्रैल में 18 साल के हो गये। अनेक देशों में विभिन्न तरह के आयोजन हुए। तिब्बतियो एवं मित्रों ने उनकी कुशलता के लिये प्रार्थनाएं कीं। साथ ही चीन पर उन्हें शीघ्र एवं बिना शर्त रिहा करने के लिये प्रदर्शन भी किये।

धर्मशाला । ताशी लुंपो विहार की आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर 32,490 अमेरिकी डालर के ईनाम की घोषणा अब भी कायम है। यह इनाम 11वें पंचेन लामा, गेदुन छ्योकि नीमा के बारे में विश्वसनीय सूचना देने वाले के लिये है। ऐसी सूचना जिससे तिब्बत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित धार्मिक हस्तियों में गिने जाने वाले युवा पंचेन लामा से किसी तरह संपर्क कायम किया जा सके।

ताशी ल्हुंपो तिब्बत के सबसे प्रतिष्ठित विहारों में से एक है। 14 मई 1995 के दिन 6 वर्षीय गेदुन छ्योकि नीमा को पंचेन लामा के रूप में दलाई लामा ने मान्यता दी थी। लेकिन इससे चिढ़कर चीन सरकार ने गेदुन छ्योकि नीमा और उनके माता पिता को हिरासत में लेकर उन्हें गायब कर दिया था। तब से चीन सरकार ने उनके बारे में कोई खबर दुनिया को नहीं दी है। लेकिन 15 मई 1996 को चीन सरकार ने स्वीकार किया था कि उसने 11वें पंचेन लामा को अपनी ' संरक्षणात्मक सुरक्षा' में रखा हुआ है।

तिब्बत की निवार्सित सरकार तथा निर्वासित तिब्बतियों का दावा है कि पंचेन लामा एवं उनके परिवारजन राजनीतिक कैदी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने गेदुन छ्योकि नीमा को 'दुनिया का सबसे कम उम्र का राजनीतिक कैदी ' घोषित किया हुआ है। कई संगठन उन्हें ' तिब्बत का चुराया हुआ बच्चा ' कहते हैं।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन 'सीटीए' ने इस बारे में यहां '11वें पंचेन लामा, गेदुन छ्योकि नीमा' पर संगोष्ठी आयोजित की। इसमें तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री प्रोफेसर समदोंग रिंपोछे ने भी विचार रखे।

उल्लेखनीय है कि अनेक प्रतिष्ठित तिब्बती गैर सरकारी संगठन ' पंचेन लामा बचाओ ' अभियान चला रहे हैं। यह संगोष्ठी इसी अभियान के तहत आयोजित की गई थी।

पंचेन लामा की मौजूदा स्थिति एवं कुशलता के बारे में पिछले कुछ साल में तरह तरह की विरोधाभासी खबरें सामने आई हैं। उनके बारे में अनेक तरह की अटकलें सुनने को मिली हैं हालांकि आधिकारिक स्तर पर कुछ भी पता नहीं चल पाया है।

वाशिंगटन में बाइक रैली

11वें पंचेन लामा को मुक्त करने की मांग को लेकर तिब्बत युवा कांग्रेस के मिनेसोटा प्रखंड की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया।

यह रैली 20 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी स्थित चीनी दूतावास के सामने से शुरू हुई। इसमें 25 मोटरसाइकिल सवारों ने भाग लिया जिनमें एक 19 साल की युवती तथा 70 साल का एक वृद्ध भी शामिल है।

रैली से एक दिन पहले इसमें भाग ले रहे चालकों ने कैपिटल हिल में कांग्रेसमैन जिम रमस्टेड, कैथ एलिसन, सीनेटर एमी क्लोबाउचर तथा सीनेटर नार्म कोलमेन से मुलाकात की। उन्होंने तिब्बतियों की बात को पूरे मनोयोग से सुना। (आईसीटी)

धर्मशाला में आयोजन

11वें पंचेन लामा के 18वें जन्मदिन पर त्सुगला खांग मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निर्वासित तिब्बती सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री सोनम तोपग्याल थे।

परम पावन पंचेन लामा गेदुन छ्योकि नीमा अब आधिकारिक रूप से 18 साल के हो गये हैं। इसका मतलब यही हुआ कि चीन के या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वे खुद के बारे में फैसला करने के अधिकारी हो गये हैं। वे इस बारे में अब खुद फैसला कर सकते हैं कि उन्हें चीन की कथित ' संरक्षणात्मक अभिरक्षा ' की जरूरत है या नहीं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि पंचेन लामा को इस तरह की

सुरक्षा ही गई है। इस अवसर पर चार संगठनों ने ' रन फार पंचेन लामा ' का आयोजन किया।

युवा कांग्रेस का वक्तव्य

विश्व समुदाय, चिंतित सरकारें तथा चीन के मानवा–धिकार संगठन लंबे समय से 11वें पंचेन लामा की कुशलता आदि के बारे में जानकारी मुहैया कराने तथा स्वतंत्र निरीक्षकों को उनसे एवं उनके परिवार से मिलने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन चीन की सरकार ने इस तरह की किसी पहल की इच्छा नहीं दिखाई है।

इसके विपरीत सरकार की मंशा अंतरराष्ट्रीय नियमों, सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा अन्य कानूनों को ताक पर रखने की रही है। वह अपनी इसी नीति को आगे बढ़ा रही है।

इस अवसर पर तिब्बती युवा कांग्रेस ने कहा है कि वह पंचेन लामा के 18वें जन्मदिन पर चीन की सरकार से मांग करती है कि उन्हें बिना किसी शर्त के तत्काल रिहा किया जाये। हम चीन की सरकार से आग्रह करते हैं कि पंचेन लामा को ताशी ल्हुंपो विहार में आवश्यक धार्मिक शिक्षा दीक्षा की सुविधा मुहैया कराई जाये। इसके अलावा हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह करते हैं कि वे इस संबंध में चीन पर दबाव बनाये रखें।

पंचेन लामा के मठ ताषी ल्हुंपो से जारी बयान में कहा गया कि हालांकि हम यह वर्षगांठ भारी मन के साथ मना रहे हैं फिर भी सभी भिक्षु परम पावन पंचेन लामा के 18वें जन्मदिन पर उनके स्वस्थ एवं कुशल होने की मंगल कामना करते हैं।

दुख की बात है कि तमाम तरह के अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद चीन ने युवा पंचेन लामा को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा हुआ है।

अमेनस्टी इंटरनेशनल ने सवाल उठाये

वाशिंगटन। मानवाधिकार संगठन अमेनस्टी इंटरनेशनल ने चीन की सरकार के साथ हुई एक बैठक में पंचेन लामा के बारे में चिंता जताई। चीनी अधिकारियों को बताया गया कि पंचेन लामा के लगातार गायब रहने और चीन सरकार द्वारा उनके बारे में किसी तरह की सूचना न देने और किसी को उनसे मिलने की अनुमति न देने से दुनिया भर में उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता बनी हुई है।

वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के साथ अपनी पहली आधिकारिक बैठक में एमनेस्टी इंटरनेशनल के अमेरिका कार्यालय ने यह मुद्दा उठाया। उस समय वे छह साल के थे।

इस अवसर पर भारत समेत दुनिया भर के दर्जनों देशों में पंचेन लामा की रिहाई के लिए प्रदर्शन किए गए और प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। नई दिल्ली में भारत के कई तिब्बत समर्थक संगठनों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और लंबे धरने तथा प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। ऐसे ही समाचार न्यूयार्क, लंदन, पैरिस, टोक्या और अन्य स्थानों से आए हैं।

11वें पंचेन लामा के बारे में तथ्य

– जनवरी 1989 में चीन सरकार ने 10वें पंचेन लामा को कई साल के बाद बीजिंग से तिब्बत में अपने मठ ताशी लुपो जाने की अनुमति दी। लेकिन ताशी लुपो में उन्होंने एक सार्वजनिक ध ार्मिक सभा में तिब्बत पर चीन की नीति की जोरदार आलोचना की। इसक अगले ही दिन रहस्यमय परिस्थितियों में उनके निधन का समाचार चीन सरकार ने जारी किया।

– नए पंचेन लामा के अवतार की खोज के लिए गठित चीन सरकार के दल ने छह साल के गेदुन छ्योकि नीमा को ढूंढा जिसे 14 मई, 1995 को परम पावन दलाई लामा ने दसवें पंचेन लामा के अवतार के रूप में मान्यता दी। चीन को यह बात पसंद नहीं आयी। उसने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।

– 17 मई 1995 को, 11वें पंचेन लामा की घोषणा के तीन दिन बाद ही गेदुन छ्योकि नीमा अपने परिवार के साथ लापता हो गये।

– नवंबर 1995 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले एक 'खोजी दल' ने एक अन्य बालक ग्यालसेन नोरबू को लाटरी के रास्ते चुनकर चीन के पिठ्ठू पंचेन लामा के रूप में पेश किय।

– दलाई लामा, निर्वासित तिब्बती सरकार, पंचेन लामा के अन्य अनुयायी तथा तिब्बत समर्थक संगठन गेदुन छ्योकि नीमा को ही 11वां पंचेन लामा का असली अवतार मानते हैं।

विश्व समुदाय तथा चीन के मानवा – धिकार संगठन लंबे समय से 11वें पंचेन लामा की कुशलता आदि के बारे में जानकारी मुहैया कराने तथा स्वतंत्र निरीक्षकों को उनसे एवं उनके परिवार से मिलने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। लेकिन चीन की सरकार ने इस तरह की किसी पहल की इच्छा नहीं दिखाई है। इसके विपरीत सरकार की मंषा अंतरराष्ट्रीय नियमों तथा अन्य कानूनों को ताक पर रखने की रही है।

पंचेन लामा की रिहाई के एक कार्यक्रम में एक रेडियो पत्रकार – तिब्बत के लिए खबर

अनेक रेडियो सेवाओं के खिलाफ चीनी जैमिंग अभियान की निंदा

वायस आफ तिब्बत सहित अनेक विदेशी शार्ट वेव रेडियो सेवाओं को जाम कर रखा है चीन ने

संगठन ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन का आह्वान किया है ताकि चीन को इस उल्लंघनकारी कदम से रोकने के लिये दबाव बनाया जा सके। संगठन ने चीन के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र में पारित अनके प्रस्तावों के तहत चीन से नागरिक अधिकारों के सम्मान की मांग की है।

द फाउंडेशन वायर आफ तिब्बत ने चीन द्वार रेडियो ' जैमिंग' का विरोध करने के लिये अभियान शुरू किया है।

चीन ने ' वायस आफ तिब्बत' तथा अन्य ' विदेशी ' शार्ट वेव रेडियो सेवाओं को दस साल से अधिक समय से ' जैम' कर रखा है। संगठन ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन का आह्वान किया है ताकि चीन को इस उल्लंघनकारी कदम से रोकने के लिये दबाव बनाया जा सके।

संगठन ने चीन के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र में पारित अनके प्रस्तावों के तहत चीन के अधिकारियों से मांग की है कि वे नागरिक अधिकारों का सम्मान करते हुए अपनी इस हरकत को तुरंत रोकें। संगठन का कहना है कि रेडियो की जैमिंग के जरिये चीन अन्य देशों के नागरिक अधिकारों को भी बाधित कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि वायस आफ तिब्बत (वीओटी) एक गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) रेडियो है जिसका पंजीकरण 1995 में नार्वे में हुआ। वीओटी अपनी दैनिक सेवाओं में तिब्बत के बारे में अनसेंसर्ड कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इसके आलवा उसका चीनी मेंडरिन भाषा का कार्यक्रम भी है।

वीओटी ने 14 मई 1996 को भारत, नेपाल, तिब्बत एवं चीन में प्रसारण शुरू किया था। लेकिन कुछ सप्ताह में ही चीन ने वीओटी के प्रसारणों की जैमिंग शुरू कर दी। चीन ने वीओटी को ट्रांसमीटर किराये पर देने वाले एफईबीए रेडियो को वीओटी के साथ अपने करार को समाप्त करने को कहा है। चीनी अधिकारियों ने एफईबीए को चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर उनके अन्य प्रसारणों को भी जैम कर दिया जायेगा।

वर्ष 2000 से ही चीन ने वीओटी के प्रसारणों की जैमिंग को और कड़ा कर दिया है। चीन के अधिकारी आजकल वीओटी के प्रसारण को जैम करने के लिये अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए दो समान जैमिंग का इस्तेमाल करते हैं।

तिब्बत के जंगल में भीषण आग

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के जंगलों में 19 अप्रैल को भीषण आग लग गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह आग दक्षिण पूर्वी तिब्बत के नियांगची खंड में बाई कस्बे से चार किलोमीटर दूर कल शाम 5 . 10 बजे लगी और वहां धुएं के विशाल गुबार देखे गये।

सिन्हुआ के अनुसाार लगभग 4,000 अग्निशमन कर्मचारियों ने इस आग पर काबू करने की कोशिश की। खंड के प्रशासनिक कार्यालय के उपायुक्त युल्हा ने बताया कि तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली और शुक्रवार सुबह तक यह चार से पांच किलोमीटर और फैल चुकी थी।

अग्निशमन अधिकारियों ने इस आग को गांवों, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 318 तक पहुंचने से रोकने के लिये तीन 'फायरब्रेक' खोदे।

टी सी एच आर डी की कैदियों पर नयी रिपोर्ट जारी

मानवाधिकार एवं लोकतंत्र के लिये तिब्बती केंद्र (टी सी एच आर डी) ने एक रिपोर्ट 'तिब्बत के कैदी' जारी की है। इस रिपोर्ट को जेनेवा में मानवाधिकार परिषद् के चौथे सत्र के अवसर पर 23 मार्च को आयोजित एक अन्य आयोजन में जारी किया गया।

इस रिपोर्ट में अपनी अभिव्यक्ति, विचार एवं विवेक के मूल मानवाधिकार को निभाने में तिब्बती लोगों के समक्ष आ रही मुश्किलों का जिक्र किया गया है।

तिब्बती, चीन की एक ऐसी तानाशाह सरकार के

शिकार हैं जो मूल मानवाधिकार का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को मनमाना दंड देने को मुक्त है। मौजूदा विधि व्यवस्था के तहत तिब्बतियों को एक संक्षिप्त न्यायिक प्रक्रिया या के तहत जेल भेजा जा सकता है या प्रशासनिक गिरफ्तारी में रखा जा सकता है जो चार साल तक की हो सकती है।

चीन स्वतंत्र संगठनों को जेलों, श्रम केंद्रो तथा हिरासत केंद्रों का चरणबद्ध एवं नियमति दौरा करने की अनुमति नहीं देता इसलिये राजनीतिक कैदियों की सही–सही संख्या बताना लगभग असंभव ही है। टीसीएचआरडी का कहना है कि फिलहाल 116 तिब्बती कैदी जानकारी में हैं जिनमें से 51 को दस साल या अधिक की जेल की सजा दी गई है।

तिब्बत में कुल राजनीतिक कैदियों में से 80 प्रतिशत संख्या भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों की है। वैसे भी कैदियों की इस संख्या के वास्तव में काफी अधिक होने का अनुमान है।

इस रिपोर्ट में ज्ञात मौजूदा तिब्बत कैदियों में से अधिकतर का ब्यौरा दिया गया है।

तिब्बत से पलायन के खतरों आईसीटी ने रिपोर्ट जारी की

तिब्बत के लिये अंतरराष्ट्रीय अभियान (आईसीटी) की एक नवीनतम रिपोर्ट में चीनी दमन से बचने के लिये हिमालय को पार करने वाले तिब्बतियों के लिये खतरों का ब्यौरा दिया गया है। इसमें गत सितंबर की उस दिल दहलाने वाली घटना का भी जिक्र किया गया है जिसमें नांगपा दर्रे पर चीनी सैनिकों द्वारा तिब्बतियों के एक समूह पर की गई गोलीबारी में एक भिक्षुणी मारी गई थी।

इस घटना को वहां मौजूद विदेशी पर्यटकों ने फिल्मा लिया था। अमेरिका एवं यूरोपीय संघ ने भी इसके लिये चीन की आलोचना की थी। निर्वासित जीवन के लिये भागने वाले तिब्बतियों से चीनी सैनिकों के दुर्दांत व्यवहार की यह अपनी तरह की पहली डाक्यूमेंटरी है।

आईसीटी की यह रपट 'डेंजरस क्रासिंग' 12 फरवरी को प्रकाशित हुई। यह दस्तावेज निर्वासन की कोशिश में तिब्बत से बाहर जाने की कोशिश करने वाले तिब्बतियों पर चीनी सीमा सैनिकों द्वारा गोलीबारी, तिब्बतियों के साथ दुर्व्यवहार तथा पकड़े जाने वाले तिब्बतियों को सजा के नये साक्ष्य है। बर्लिन में इस रिपोर्ट को तिब्बत समर्थक अभिनेता रिचर्ड गेअर तथा

नांग्पा ला में चीनी गोलीबारी के विरोध में एक चीनी अमेरिकी नागरिक : तिब्बत के लिए दर्द

रोमानिया के कैमरामैन सर्गइ मातेई ने जारी किया। मातेई ने ही नांगपा ला गोलीबारी घटना का फिल्मांकन किया था। आईसीटी की उपाध्यक्ष मेरीबेथ मर्क ने कहा,' अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं अन्य सरकारों ने तिब्बत–नेपाल सीमा पर एक युवा भिक्षुणी की हत्या पर अपने विरोध को चीन के समक्ष दर्ज कराया है।'

ऐसा अनुमान है कि हर साल 2,500 से 3,000 तिब्बती हिमालय को पार करते हुए नेपाल से भारत पहुंचते हैं। उनकी यात्रा का एक उद्देश्य परमपावन दलाई लामा के दर्शन करना और आजादी में नया जीवन शुरू करना होता है। इनमें से एक तिहाई से अधिक बच्चे होते हैं जिन्हें उनके मां – बाप बेहतर शिक्षा के लिये बाहर भेजते हैं। इसी तरह भिक्षु एवं भिक्षुणियां अपने धार्मिक क्रिया कलापों को स्वतंत्र ढंग से संपन्न करने के लिये निर्वासन का फैसला करते हैं।

तिब्बत से चीन को बिजली

तिब्बत में नए चीनी नागरिकों को बसाने के लिए वहां नए बिजलीघरों के निर्माण का सिलसिला जारी है। टीएआर का बिजली उत्पादन 2006 में बढ़कर 15 लाख मेगावाट को पार कर गया जो 2005 के बिजली उत्पादन की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। तिब्बत डेली की एक रपट के अनुसार उक्त साल में स्थानीय बिजली ब्यूरो की बिक्री 21 प्रतिशत बढ़कर 5656 करोड़ डालर हो गई। इसका शुद्ध लाभ 14.6 प्रतिषत बढ़कर 74.2 करोड़ डालर हो गया।

तिब्बत के विशाल जल भंडार का चीनी इलाकों के लिए दोहन करने की कई चीनी याजनाएं हैं जिनमे नदियों का प्रवाह चीन की ओर मोड़ना भी शामिल है।

रिपोर्ट 'डेंजरस क्रासिंग' 12 फरवरी को प्रकाशित हुई। यह दस्तावेज निर्वासन की कोशिश में तिब्बत से बाहर जाने वाले तिब्बतियों पर चीनी सीमा सैनिकों द्वारा गोलीबारी, तिब्बतियों के साथ दुर्व्यवहार तथा पकड़े जाने वाले तिब्बतियों को सजा की नया साक्ष्य है।

तिब्बत की कहानी

1. काठमांडो में दुनिया की सबसे ऊंची पद्मसंभव, अमिताभ और अवलोकितेश्वर की मूर्ति
2. 12 साल से चीन की हिरासत में गुम पंचेन लामा के 18वें जन्मदिन पर दुनिया भर में
3. लंदन में पंचेन लामा के 18वें जन्म दिवस पर उनकी रिहाई की मांग करते हुए तिब्ब
4. पंचेन लामा की रिहाई के लिए न्यूयार्क में तिब्बत समर्थकों ने एक प्रदर्शन का आयोज
5. धर्मशाला में एक समारोह के दौरान 24मई के दिन साक्य त्रिजिन रिंपोछे (बाएं) और
6. मसूरी में तिबेतन होम्स फाउंडेशन की 40वी सालगिरह के मौके पर वहां 20 साल से
7. ब्रसेल्स में 13–14 मई के दिन तिब्बत समर्थक संगठनों के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
8. तिब्बत समर्थक संगठनों के पांचवें ब्रसेल्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्थानीय तिब्बती सम
9. भारत और चीन के बीच वार्ता के लिए चीनी प्रतिनिधि की दिल्ली यात्रा के समय दिल
10. तिब्बत के कुछ भागों में इन दिनों एक अजीब बीमारी केसिन–बेक का प्रकोप चल र

PAGE -08-09 PHOTO-I

PAGE -08-09 PHOTO-H

—— कैमरे की जुबानी

यों को 21 मई के दिन अनावरण किया गया।।
उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हुए। पैरिस प्रदर्शन का एक दृश्य।
त समर्थक।
न किया।
र्मा पा जी के साथ परमपावन दलाई लामा।
कार्य करने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान एक कार्यदल की बैठक।
ाज ने एक रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया।
ली के तिब्बती नागरिकों और तिब्बत समर्थकों ने एक साझा प्रदर्शन किया।
हा है। यह एक फंगस के कारण होती है।

(फ़ोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में। फोटो 7 और 8 : विजय क्रान्ति)

PAGE -08-09 PHOTO-G

PAGE -08-09 PHOTO-F

पुस्तक–समीक्षा

निर्वासन में तिब्बती ज़िंदगी की रोचक गाथा

नीरजा माधव के हिंदी उपन्यास 'गेशे जम्पा' में निर्वासन के दर्द और संघर्ष का सुंदर चित्रण

सारनाथ की पृष्ठभूमि वाले उनके इस उपन्यास की कहानी वहां की महाबोधि विद्या परिषद द्वारा चलाए जाने वाले एक तिब्बती स्कूल और कुछ स्थानीय तिब्बती शरणार्थियों के आसपास बुनी हुई है। इसी छोटे से समाज के संदर्भ से लेखिका ने भारत में रहने वाले तिब्बती समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृति ज़िंदगी का एक ऐसा परिचय दिया है जो हर पन्ने पर दिल को छू लेने की ताकत रखता है।

हालांकि तिब्बती शरणार्थी समाज को भारत में रहते हुए अब पचास साल होने को हैं और यह समाज राजनीतिक और सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों से लगातार चर्चा में भी रहा है। पर यह देखकर हैरानी होती है कि भारतीय साहित्य में इस समाज को लेकर लिखी गई साहित्यिक रचनाओं, खासकर उपन्यासों की संख्या उंगलियों की गिनती भी पूरी नहीं करती।

1959 में भारत पहुंचे तिब्बती शरणार्थियों की दयनीय हालत पर शुरू–शुरू में कई बड़े हिंदी लेखकों की कुछ कहानियों और स्मरणों में हींग और स्वेटर बेचने वाले तिब्बती विषयवस्तु जरूर रहे। लेकिन बाद में श्री बल्लभ डोभाल के 'तिब्बत की बेटी' उपन्यास के बाद हिंदी में बरसों तक इस विषय पर कोई उपन्यास पढ़ने सुनने को नहीं मिला *(अज्ञानता के लिए क्षमा याचना सहित)*।

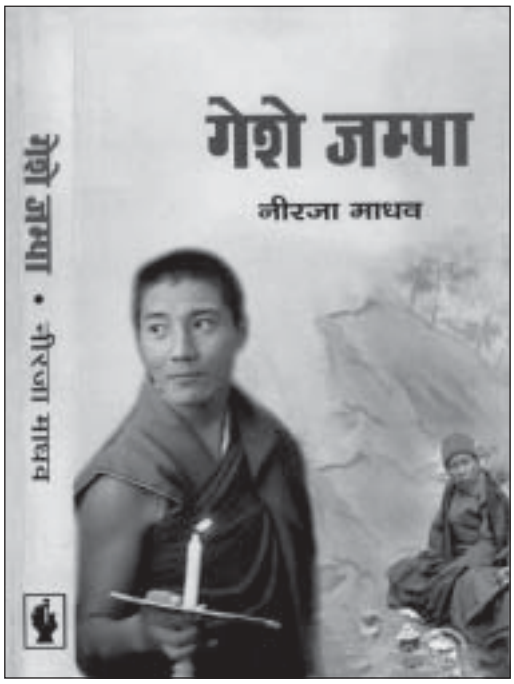

कुछ महीने पहले सुश्री नीरजा माधव के उपन्यास 'गेशे जम्पा' (सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली) ने इस रिक्तता को बहुत अच्छे रंगों से भरा है। सारनाथ की पृष्ठभूमि वाले उनके इस उपन्यास की कहानी वहां की महाबोधि विद्या परिषद द्वारा चलाए जाने वाले एक तिब्बती स्कूल और कुछ स्थानीय तिब्बती शरणार्थियों के आसपास बुनी हुई है। इसी छोटे से समाज के संदर्भ से लेखिका ने भारत में रहने वाले तिब्बती समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृति ज़िंदगी का एक ऐसा परिचय दिया है जो हर पन्ने पर दिल को छू लेने की ताकत रखता है।

इस उपन्यास की कहानी के मुख्य पात्र स्कूल के प्रधान गेशे जम्पा हैं जो एक तिब्बती भिक्षु और विद्वान होने के साथ–साथ तिब्बत की निर्वासन सरकार में एक मंत्री भी हैं। दूसरा मुख्य पात्र स्कूल में हाल ही में नियुक्त भारतीय अध्यापिका देवयानी है जिसके मन में तिब्बती समाज के लिए ढेर सारी करुणा और सहानुभूति भी है और गेशे जम्पा के प्रति आकर्षण भी। लेकिन यह आकर्षण उनके प्रति आदर और तिब्बती आजादी के संघर्ष में उनकी लगन से उपजा स्नेह ज्यादा है और स्त्री–पुरुष वाला व्यक्तिगत प्रेम कम।

अगर आप भारत में रहने वाले तिब्बती समाज और उसके राजनीतिक संघर्ष के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उपन्यास के शुरुआती पन्नों में ही आपको समझ आ जाएगा कि लेखिका का मन इस समाज के प्रति सहानुभूति, करुणा और अनुराग से भरा हुआ है। यह अनुराग कहानी के अलग–अलग चरित्रों की आपसी बातचीत, खासकर नोंकझोंक, के बहाने व्यक्त होने का रास्ता बनाता चलता है। कई बार ऐसा लगता है मानो लेखिका खुद को देवयानी के रास्ते व्यक्त करना चाह रही है।

उपन्यास की कहानी के माध्यम से लेखिका ने काफी विस्तार से भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों की तंग आर्थिक हालत; उनके मन में तिब्बती आजादी की ललक; तिब्बत के भीतर चीनी अत्याचारों के कारण उन्हें वहां से भागने पर मजबूर करने वाली परिस्थितियों; इस कारण पैदा होने वाली त्रासद भावनात्मक स्थितियों; निर्वासन के वातावरण से तिब्बती युवाओं के एक वर्ग में पैदा होने वाली कुंठाओं; कुछ भारतीयों के मन में कभी कभार तिब्बती शरणार्थियों के प्रति उठने वाली आशंकाओं और; चीन सरकार की ओर से शरणार्थियों के खिलाफ चलाए जाने वाले कुचक्रों का बहुत बारीकी से वर्णन किया है।

उदाहरण के लिए अनाथ शरणार्थी बच्चों को पालने वाली भिक्षुणी लोये दोलमा के भिक्षुणी बनने की कहानी के रास्ते लेखिका ने बहुत सहज तरीके से बताया है कि किस तरह तिब्बत में चीनी सैनिकों के आ धमकने और उनके अत्याचारों के कारण आम लोगों को देश

से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। भिक्षुणी लोये दोलमा की शरण में सौंपे गए नन्हें बालक ताशी का रह–रहकर मां को याद करके रोना पाठक को आसानी से बता देता है कि आज पचास साल बाद भी तिब्बत में चीनी अत्याचारों और तिब्बतियों की दुर्दशा का हाल यह है कि पांच साल के छोटे से बच्चे को उसकी मां इस उम्मीद से किसी के हाथ भारत भाग जाने के लिए भेज देती है कि वहां दलाई लामा के किसी स्कूल में अच्छी शिक्षा पाकर वह इंसानों जैसी जिंदगी पा जाएगा। इसी तरह गेशे जम्पा के मौसा मग्पा के चरित्र के माध्यम से उपन्यास पाठक को आसानी से यह बता देता है कि तिब्बत में विदेशी चीनी शासन के खिलाफ संघर्ष में वहां की युवा पीढ़ी ने खासी भूमिका निभाई है।

उपन्यास का एक और रोचक पहलू शीतल पटेल और देवयानी के भाई दीपेश जैसे पात्र हैं। इन पात्रों के माध्यम से लेखिका ने भारतीय समाज के मन में तिब्बती शरणार्थियों के बारे मे उठने वाली आशंकाओं को भी बहुत अच्छा स्वर दिया है और इनके निवारण के लिए उसने देवयानी के तर्कों का भी प्रभावकारी इस्तेमाल किया है। शीतल पटेल और उसके तिब्बती दोस्तों की गंगा पार एक वीरान टापू पर ड्रग पार्टी और नशे में उनकी नोंकझोंक के माध्यम से लेखिका ने निर्वासन में रहने वाली तिब्बती युवा पीढ़ी की कुंठाओं को भी ईमानदार स्वर दिया है। पर इसके साथ–साथ तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता टन्चू धोंदुप के रास्ते लेखिका ने पाठकों को यह बताने का प्रयास भी किया है कि युवा तिब्बती शरणार्थियों की मुख्य धारा तिब्बती आजादी के संघर्ष में बहुत सक्रियता से जुटी हुई है।

इस विवरण को देखकर लगता है कि लेखिका ने इस उपन्यास की तैयारी में इस समाज के बारे में काफी गंभीरता से शोध किया है। कई स्थानों पर तिब्बती भोजन, त्यौहारों और सामाजिक व्यवहार की बारीकियों का विवरण इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन तिब्बती नामों के मामले में यह शोध सामान्य से कुछ ज्यादा ही किताबी हो गया है। ज्यादातर नामों को इतने शास्त्रीय ढंग से लिखा गया है कि वे प्रचलित शैली के सामने बनावटी और इतने पराए लगने लगते हैं कि आम तिब्बतियों को भी स्वीकार करना मुश्किल लगे। हालांकि यह कमी उपन्यास को कमजोर तो नहीं करती पर प्रचलित शैली में नामों के लिखने से पाठक के लिए उनकी स्वीकार्यता आसान की जा सकती थी। उदाहरण के लिए फुङ्चुङ् की जगह प्रचलित नाम फुंचोग या फुंसोग और सीरीङ् की जगह सेरिंग जैसे आसान और प्रचलित नाम पाठक के लिए पढ़ने और याद रखने में आसान रहते।

इसी तरह कुछ स्थानों पर सामान्य पात्रों की बातचीत में कठिन भाषा में गंभीर राजनीति टिप्पणियां एक उपन्यास के संदर्भ में कुछ भारी लगती हैं। लेकिन उपन्यास के अपने राजनीतिक संदर्भ और लेखिका के उद्देश्य को देखते हुए इस बोझिलता को स्वीकार किया जा सकता है।

कुल मिलाकर यह उपन्यास हिंदी पाठक को प्रचलित लेखन प्रकाशन की धारा से कुछ दूर ले जाकर एक ऐसे विषय से नया और रोचक परिचय कराने में सफल रहा है जो कहने को भले ही हिंदी पाठक के लिए एक पुराना विषय हो पर जिसके बारे में लेखकों ने अब तक केवल आधा अधूरा न्याय किया है। इसके लिए नीरजा माधव बधाई की पात्र हैं।

नीरजा माधव हिंदी की एक अनुभवी लेखिका हैं। इससे पहले उनके दो उपन्यास और 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वह आजकल वाराणसी के आकाशवाणी केंद्र में कार्यक्रम अधिशासी के रूप में काम कर रही हैं। उन्हें अपने लेखन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, भारतेंदु अकादमी और अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

— विजय क्रान्ति

नीरजा माधव की रचनाएं

(कहानी संग्रह) – 'चिटके आकाश का सूरज, 'अभी ठहरो अंधी सदी', आदिमंध तथा अन्य कहानियां', 'पथदंश', 'चुप चंतारा, रोना नहीं'

(उपन्यास) – 'तेभ्यः स्वधा', 'यमदीप', 'गेशे जम्पा'

(पुस्तक) –'रेडियो का कलापक्ष'

(पुरस्कार) – उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान, भारतेंदु अकादमी, अखिल भारतीय विद्वत परिषद

भिक्षुणी लोये दोलमा की शरण में सौंपे गए नन्हें बालक ताशी का रह–रहकर मां को याद करके रोना पाठक को आसानी से बता देता है कि आज पचास साल बाद भी तिब्बत में चीनी अत्याचारों और तिब्बतियों की दुर्दशा का हाल यह है कि पांच साल के छोटे से बच्चे को उसकी मां इस उम्मीद से किसी के हाथ भारत भाग जाने के लिए भेज देती है कि वहां दलाई लामा के किसी स्कूल में अच्छी शिक्षा पाकर वह इंसानों जैसी जिंदगी पा जाएगा।

फिल्म ड्रीमिंग ल्हासा का एक दृश्य : चीन का दुःस्वप्न

तिब्बत पर भारतीय फिल्म से चीन हुआ बैचेन

विश्व स्तर पर प्रदर्शन रोकने की कोशिश में

इस फिल्म को समकालीन तिब्बत पर पहली अच्छी फिल्म बताया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि चीन इससे विचलित है और वह इसके विदेशों में प्रदर्शन को रोकने की कोशिश में है। उसको चिंता है कि इस फिल्म से ओलंपिक खेलों से पहले तिब्बत की दुदर्शा पर नये सिरे से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है।

मलेशिया सन, 14 अप्रेल समकालीन तिब्बत पर बनी एक फिल्म से चीन सरकार की भौंहे तन गई और ऐसी खबरें हैं कि वह इसके विश्व स्तर प्रदर्शन पर रोक की कोशिश में है।

इस फिल्म ' ड्रीमिंग ल्हासा' के प्रोड्यूसर रिचर्ड गियर हैं जबकि इसे बनाया भारतीय फिल्मकर्मी रितू सरीन और उनके तिब्बती पति तेनजिंग सोनम ने है। इस फिल्म को न्यूयार्क के इमेजिनेशन थियेटर में दिखाया गया। इसके अलावा अमेरिका के कई और प्रमुख शहरों में इसके प्रदर्शन की भी योजना है।

इस फिल्म में निर्वासित तिब्बती समुदाय के दुःख को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें सोनम का अपना अनुभव भी शामिल है जो उस पहली पीढ़ी से सम्बद्ध है जिसका जन्म भारत में हुआ और अपनी अधिकतर युवावस्था पश्चिम में गुजारी।

इस फिल्म को समकालीन तिब्बत पर पहली अच्छी फिल्म बताया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि चीन इससे विचलित है और वह इसके विदेशों में प्रदर्शन को रोकने की कोशिश में है। उसको चिंता है कि यह फिल्म बीजिंग 2008 ओलंपिक खेलों से पहले तिब्बत की दुदर्शा पर नये सिरे से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि चीनी अधिकारियों ने 2005 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल के आयोजकों पर दबाव डाला था कि वे ' ड्रीमिंग ल्हासा' का प्रदर्शन नहीं करें लेकिन आयोजकों ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन चीन ने 2005 में ही पुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में इसका प्रदर्शन नहीं होने दिया।

फिल्म का जवाब फिल्म से देने की कवायद के तहत चीन के अधिकारी ' द साइलेंट होली स्टोन्स' का प्रदर्शन करने की अनुमति दे रहे हैं। वे इसे पहली तिब्बती फीचर फिल्म के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। जिस दिन न्यूयार्क में ड्रीमिंग ल्हासा का प्रदर्शन हो रहा था उसकी दिन एक अन्य थियेटर में द साइलेंट होलीस्टोन्स भी दिखाई गई।

चीनी विद्वान ने कहा : तिब्बत हमारा नहीं

हांगकांग (वेंकटेसन वेंबू)। चीन के विख्यात इतिहासकार एवं चीन की इतिहास की आधिकारिक पाठ्यपुस्तकों पर परामर्ष देने वाले समिति के सदस्य ने कहा है कि यह दावा करना कि प्राचीन बौद्ध साम्राज्य ''हमेशा ही चीन का अंग'' रहा है, इतिहास की अवज्ञा होगा।

इंस्टीट्यूट आफ चाइनीज हिस्टारिकल ज्योग्राफी तथा चिंघाई (आम्दो) स्थित फुडान यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर फार हिस्टारिक्ल ज्योग्राफी स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर जी चियांग्सींग (62) ने पत्रिका चाइना रिव्यू में एक आलेख में यह बात कही है। इसमें उन्होंने कहा है कि तांग वंश (सातवीं से दसवीं शताब्दी) के दौरान चीन कितना विस्तारित था, इस पर विचार करते समय 'हम चिंघाई–तिब्बत पठार को शामिल नहीं कर सकते जहां तुबो/तुफान का शासन था।'

जी ने कहा है कि तुबो/तुफान,'तांग वंश से स्वंतत्र प्रभुत्व वाले थे। कम से कम उन पर तांग वंश का शासन तो नहीं था।' जी ने तर्क दिया है कि ऐसा नहीं होता तो तांग शासक को तिब्बती राजा स्रोंग्तसेन गोंपो से राजकुमारी वेन चेंग से 'विवाह' की पेशकश करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा है,'यह कहना कि तांग वंश के काल से ही तिब्बत चीन का भाग रहा है, इतिहास की अवज्ञा होगी।'

भारत की नेपाल को रेललाईन की पेशकश

भारतीय अधिकारी पड़ोसी देश नेपाल तक रेललाईन बिछाने के लिये पांच विकल्पों पर इन दिनों गंभीरता से विचार कर रहे हैं। चीन की नेपाल सीमा तक रेल

लाईन बिछाने की मंशा ने भारतीय रेल अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से सोचने को विवश कर दिया है। चीन ने तिब्बत को पहले रेल लाईन को गत वर्ष शुरू किया था और वह अब इसका विस्तार नेपाल सीमा तक करना चाहता है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन द्वारा रेल लाईन के नेपाल सीमा तक विस्तार के विचार के बाद रेल मंत्रालय ने नेपाल को रेल लाईन के लिये व्यावहार्यता अध्ययन को 'शीर्ष प्राथमिकता ' दे दी है।

चीन ने चिंघाई प्रांत से तिब्बत की राजधानी ल्हासा के बीच 1,114 किलोमीटर लंबी रेल लाईन की शुरुआत गत वर्ष जुलाई में की थी। यह दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाईन है। नेपाल ने गत साल कहा था कि चीन इस लाईन का विस्तार नेपाल में करना चाहता है।

भारत के एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने समाचार पत्र से कहा, ' हालांकि ल्हासा–नेपाल रेल संपर्क न तो तकनीकी रूप से व्यावहारिक है और न ही वित्तीय रूप से उपयोगी होगा लेकिन इस रेल लाईन की रणनीतिक महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता।

चीन की भारतीय राज्य सिक्किम के पास स्थित तिब्बती कस्बे छोमो तक अगले दस साल में रेल लाईन बिछाने की योजना भी है।

उल्लेखनीय है कि भारत एवं चीन ने प्रत्यक्ष कारोबार को बहाल करने के लिये सीमा पर नाथू–ला दर्रे को खोलने पर पिछले साल सहमति जताई थी। पर भारत सरकार को अब यह चिंता सताने लगी है कि कोलकाता तक जाने वाली इस सड़क के चीनी इस्तेमाल से भारत के सात उत्तर–पूर्वी राज्यों और शेष भारत के संपर्क को गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा।

तिब्बत के छायाचित्रों का अनूठा स्लाइड शो

धर्मषाला। तिब्बतियों के तीन दशक के इतिहास को दर्शाते फोटो चित्रों का प्रदर्शन यहां एक स्लाइड शो के जरिये किया गया। इन अनूठे फोटो का स्लाइड शो प्रदर्शन रविवार को शुरू हुआ। ये फोटो 1920 से 1950 के दौरान के हैं और इन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने खींचा था। इसमें तत्कालीन तिब्बत की संस्कृति एवं विरासत की अनूठी झांकी मिलती है।

पिट रिवर म्यूजियम एवं ब्रिटिश म्यूजियम (इंग्लैंड) ने एक परियोजना 'तिब्बत विज्युअल हिस्ट्री आनलाइन 1920 – 1950' के तहत इन फोटो को एक वेबसाइट में संकलित किया है।

पिट रिवर म्यूजियम के क्यूरेटर क्लेयर हेरिस ने बताया, ' पिट रिवर म्यूजियम एवं ब्रिटिश म्यूजिम में तैयार इस नयी वेबसाइट में 6,000 फोटो हैं। ये फोटो 1920 – 1950 के दौरान तिब्बत की यात्रा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों ने खींचे थे।'

उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को ये फोटो दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने यह आयोजन किया है। उन्होंने दावा किया कि इनमें से कुछ फोटो तो लोगों ने पहले कभी देखे ही नहीं।

तिब्बती कार्यकर्ताओं का ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन

लंदन, 22 मार्च। तिब्बती नागरिकों एवं उनके समर्थकों ने तिब्बत में खनन और खोज गतिविधियों में लगी ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल चाइना कोलफील्डस के लंदन स्थित मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि चीन द्वारा कब्जा समाप्त किये जाने तक यह कंपनी तिब्बत में अपनी गतिविधियों को रोक दे।

स्टूडेंट्स फार फ्री तिब्बत यूके की राष्ट्रीय समन्वयक एलिस स्पेलर ने कहा कि एक अधिग्रहित क्षेत्र में परिचालन कर सेंट्रल चाइना कोलफील्डस जैसी कंपनियां एक देश एवं वहां के लोगों के विध्वंस में योगदान कर रही हैं। उन्होंने कहा, ''आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर तिब्बतियों को अलग थलग करके रखा गया है और तिब्बत में जारी खनन इस विध्वंस का एक और हथियार बन गया है।''

तिब्बत में काम करने वाली ब्रितानी कंपनियों की संख्या में गत साल काफी बढ़ोतरी देखने को आई। बड़े पैमाने पर संसाधनों के दोहन से तिब्बती लोगों, उनकी संस्कृति तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए तिब्बती कार्यकर्ता एवं समर्थक विरोध प्रदर्शन जैसी पहल करने को विवश हुए हैं।

चीन की सरकार ने फरवरी 2007 में चिंघाई तिब्बत पठार का 4.4 करोड़ डालर के सर्वेक्षण का ब्यौरा जारी किया था। इमसें उसने 16 प्रमुख खनन भंडारों की खोज का जिक्र किया गया है। ब्रिटेन में रह रहे तिब्बती लोगों एवं उनके समर्थकों ने इस कंपनी को फोन काल, फैक्स संदेश एवं ईमेल संदेश भेजकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है।

कंपनी के स्थानीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इन संदेशों को उन्होंने चीन में कार्यरत अपने आला अफसरों को भेज दिया है।

तिब्बत में काम करने वाली ब्रितानी कंपनियों की संख्या में गत साल काफी बढ़ोतरी देखने को आई। बड़े पैमाने पर इन संसाधनों के दोहन से तिब्बती लोगों, उनकी संस्कृति तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए तिब्बती समर्थक विरोध प्रदर्शन जैसी पहल करने को विवश हुए हैं।

चीन में ओलंपिक के खिलाफ तिब्बत के एवरेस्ट बेस कैंप पर प्रदर्शन : साहसिक कदम

ओलंपिक मशाल के प्रस्तावित मार्ग को खारिज करने की मांग

ओलंपिक मशाल को तिब्बत से ले जाने की अनुमति देने का मतलब होगा कि आईओसी, चीन द्वारा तिब्बत के सैन्य कब्जे पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा रही है। आईओसी को तिब्बत तथा अन्य अधिग्रहीत क्षेत्रों पर चीनी उपनिवेशवादी शासन को उचित ठहराने की चीन की कवायद का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए।

न्यूयार्क। स्टूडेंट्स फार फ्री तिब्बत ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) से मांग की है कि वह चीन के ओलपिंक खेलों की मशाल को माउंट एवरेस्ट पर ले जाने तथा इसे तिब्बती मार्ग से ले जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दे।

आईओसी की फिलहाल बीजिंग में बैठक चल रही है जिसमें वह चीन के प्रस्तावित मशाल मार्ग के बारे में अंतिम फैसला करेगी। इसके अलावा वह मशाल को तिब्बत एवं ताइवान के मार्ग से ले जाने के प्रस्ताव पर भी फैसला करेगी।

संगठन की कार्यकारी निदेशक ल्हाडोन टेथोंग ने कहा, ' चीन को ओलंपिक मशाल को तिब्बत से ले जाने की अनुमति देने का मतलब होगा कि आईओसी, चीन द्वारा तिब्बत के सैन्य अधिग्रहण पर एक तरह से अपनी मंजूरी की मोहर लगा रही है।

टेथोंग ने कहा कि आईओसी के पास सही फैसला करने के लिये नौ दिन हैं। उन्होंने कहा कि आईओसी का नैतिक दायित्व बनता है कि वह ओलंपिक खेलों को तिब्बत तथा अन्य अधिग्रहीत क्षेत्रों पर अपने उपनिवेशवादी शासन को उचित ठहराने की चीन की कवायद का हिस्सा नहीं बनने दे।

एसएफटी कनाडा के निदेशक केट वाजनाओ ने कहा, ' आईओसी के सदस्यों के लिये यह कठिन फैसला नहीं होगा। ' उन्होंने कहा,' अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उम्मीद है कि आईओसी दिखाएगी कि वह रीढ़ विहीन नहीं है और वह चीन को ओलंपिक खेलों का इस्तेमाल अपने उपनिवेशवादी हित साधने के लिये करने की अनुमति नहीं देगी। '

उल्लेखनीय है कि 39वें ओलंपिक खेल अगस्त 2008 में बीजिंग में होने हैं। चीन ने ओलंपिक खेलों की मशाल को अगले साल दुनिया के सबसे ऊंचे हिमशिखर माऊंट एवरेस्ट पर ले जाने की योजना है।

चीन ने 1949 से तिब्बत पर जबरन कब्जा जमाया हुआ है। एसएफटी, विद्यार्थियों एवं युवाओं का संगठन है जो तिब्बती आजादी के लिये आंदोलन कर रहा है।

चीन के मीडिया प्रतिबंधों पर ओलंपिक समिति खामोश

लंदन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी के अध्यक्ष जेक रोग ने दावा किया है कि अगले साल के बीजिंग ओलंपिक खेल चीन के विकास में योगदान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा, ''खेलों के लिये वहां जाने वाले 20,000 पत्रकारों को चीन वैसा ही दिखेगा जैसा वह है।''

यहां उल्लेखनीय है कि रोगे का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि चीन में काम कर रहे घरेलू एवं विदेशी संवाददाताओं के दमन की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

ओलंपिक खेलों की तैयारियों के मद्देनजर विदेशी पत्रकारों को चीन में मुक्त रिपोर्टिंग करने की अनुमति संबंधी नियमों की स्थानीय अधिकारी खुले तौर पर अनदेखी कर रहे हैं। हाल ही में बीबीसी की फिल्म टीम को हुनान प्रांत में चुशान से निकाल बाहर किया गया क्योंकि यह टीम वहां हो रहे दंगों की रपट करने की कोशिश में थी।

विदेशी अखबारों के लिये काम करने वाले चीनी संवाददाताओं को उन मुद्दों की रिपोर्टिंग करने पर जेल की हवा खानी पड़ती है जिन्हें चीन के अधिकारी संवेदनशील बताते हैं। मजदूर प्रदर्शनों से लेकर एड्स जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग को भी चीन में 'देश विरोधी' हरकत माना जाता है। इसी तरह तिब्बत एवं सिंकियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) में समाचार संकलन की इच्छा रखने वाले विदेशी पत्रकारों को विशेष अनुमति के लिये आवेदन करना पड़ता है।

ओलंपिक प्रेस चीफ सुन वेइजिया ने सितंबर माह में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ''वे (विदेशी पत्रकार) चीन में कहीं भी सफर कर सकते हैं, किसी तरह की पाबंदी नहीं है।''

तिब्बत मुक्ति अभियान (एफटीसी) के मैट विटीकेस

ने रोगे के इस बयान पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि यह आईओसी, चीन को खेलों के दौरान मीडिया को पूरी आजादी मुहैया करने की अनुमति देने को बाध्य नहीं कर सका है। यह आईओसी की विफलता है। उन्होंने कहा, ''घरेलू एवं विदेशी पत्रकारों को ' चीन जैसा है वैसा ही'' कैसे दिखेगा जबकि उन्हें तिब्बत जैसे स्थान पर जाने के लिये भी अनुमति की जरूरत रहेगी।

फ्रांस के राष्ट्रपति उम्मीदवार : ''बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार हो''

पेरिस फ्रांस के राष्ट्रपति पद चुनावों की दौड़ के एक प्रमुख उम्मीदवार फ्रांसुआ बेइरोउ का मानना है कि फ्रांस को 2008 में होने वाले बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए।

दारफर समर्थक एक रैली को संबोधित करते हुए बेइरोउ ने कहा, ''इस दुर्घटना या जातिसंहार को रोकने से आसान कुछ भी नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''अगर यह नाटक बंद नहीं होता है तो फ्रांस को बीजिंग में होने वाले 2008 ओलंपपिक खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए।''

यूडीएफ के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार बेइरोउ ने 2005 में दारफर की एक निजी यात्रा की थी। इस सप्ताह उन्होंने फ्रांस में तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष थुप्तेन ग्यात्सो के साथ 45 मिनट की बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्हें तिब्बत की ताजा स्थिति की जानकारी दी गई।

यहां गौरतलब है कि फ्रांस की राष्ट्रीय एसेंबली में तिब्बत के मुद्दे को अच्छा खासा समर्थन हासिल है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उन सांसदों की संख्या काफी है जो तिब्बत अध्ययन समूह के भागीदार हैं।

प्राग के मेयर को एवरेस्ट पर जाने से रोका चीन ने

काठमांडो चीन ने चेक गणराज्य के एक सबसे लोकप्रिय राजनेता को माउंट एवरेस्ट का पर्वतारोहण करने से रोक दिया है। चेक राजधानी प्राग के मेयर पावेल बेम एवं पर्वतारोहियों के उनके दल को चीन के सुरक्षा अधिकारियों ने नेपाल–तिब्बत सीमा पर रोक दिया। उनकी पर्वतरोहण एजेंसी ने काठमांडो में यह जानकारी दी।

बेम ने हालांकि बाद में नेपाल की सरकार से एक और आज्ञापत्र हासिल कर लिया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ओर रवाना हो गये।

उल्लेखनीय है कि जनवरी में हुए एक मतदान में बेम को देश का सबसे लोकप्रिय राजनेता पाया गया था। जब उन्होंने हिमालय में पर्वतारोहण की तथा दो माह तक देश से दूर रहने की घोषणा की तो वहां तीव्र विरोध हुआ। ये पर्वतारोही तिब्बत की ओर से एवरेस्ट की राह पर थे तो चीन के सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इस पर बेम ने काठमांडो में नेपाल की सरकार से एक और आज्ञापत्र हासिल किया।

ओलंपिक तैयारी में चीनी मजदूरों का शोषण

अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी में जुटे चीन का विवादों से पीछा छूटता नजर नहीं आ रहा है। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठनों ने चीन पर आरोप लगाया है कि ओलंपिक खेलों की तैयारी में लगे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। यह शोषण कई मामलों में बंधुआ मजदूरी जैसा है। आरोपों में कहा गया है कि शोषण का शिकार बच्चे भी हो रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से जारी एक रिपोर्ट में ये आरोप दर्ज किये गये हैं। इनमें कहा गया है कि दक्षिणी चीन में चार ऐसे कारखाने हैं जहां कई बार मजदूरों को तय न्यूनतम मजदूरी से आधी राशि का ही भुगतान किया जा रहा है। बीजिंग ओलंपिक के कारण सारी दुनिया की निगाहें चीन पर लगी हैं।

श्रमिक संगठनों का यह भी आरोप है कि तैयारियों में लगे मजदूरों से हर दिन 15 घंटे काम लिया जा रहा है। कई जगह गैर कानूनी तरीके से बाल मजदूरी भी कराई जा रही है। एक कारखाने के बारे में तो यहां तक कहा गया है कि विद्यालयों में अवकाश के दौरान वहां 12 साल तक की उम्र के किशोरों से भी काम करवाया जा रहा है। कारखाने के मालिक की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है।

उधर, ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ब्रेंडन बारबर ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कहा है कि वह चीन को स्पष्ट निर्देश दे कि इस तरह की गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि सरकारी तौर पर होने वाले उत्पादन पर उसका कोई नियंण तो नहीं है पर इस बारे में कई मानक तय किये गये हैं। समिति ने कहा कि वे अपेक्षा करते हैं कि इन मानकों का पालन किया जायेगा।

(बीबीसी हिंदी डाट काम की रपोर्ट पर आधारित)

कुछ अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठनों ने चीन पर आरोप लगाया है कि ओलंपिक खेलों की तैयारी में लगे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। यह शोषण कई मामलों में बंधुआ मजदूरी जैसा है। आरोपों में कहा गया है कि शोषण का शिकार बच्चे भी हो रहे हैं।

बाघों की खाल से बना टैंट : चीनी बाजार के शौक

'टाइगर वाइन' पर चीन की आलोचना

'टाइगर फार्म' की आड़ में तस्करी को बढ़ावा

नेपाल में हुए अंतरराष्ट्रीय बाघ सम्मेलन में 'टाइगर बोन वाइन' नाम की एक शराब की वजह से चीन की तीखी आलोचना की गई। ऐसी खबर है कि चीन में बनने वाली 'राइस वाइन' में बाघ की खाल और हड्डियों को भिगोया जाता है और उससे यह तथाकथित 'टाइगर बोन वाइन' बनाई जाती है। शराब के शौकीनों का मानना है कि इससे उनमें ताकत आती है।

इस सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधियों ने बाघ की हड्डियों तथा चमड़ी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। जबकि बाघों की कम होती संख्या को ध्यान में रखते हुए अन्य एशियाई देश इस प्रतिबंध को बनाये रखना चाहते हैं। सम्मेलन में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई।

सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधियों ने बाघ की हड़िडयों तथा चमड़ी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। जबकि बाघों की कम होती संख्या को को ध्यान में रखते हुए अन्य एशियाई देश इस प्रतिबंध को बनाये रखना चाहते हैं।

सम्मेलन में बाघों की कम होती संख्या की कई वजहें गिनाई गईं लेकिन चीन के 'टाइगर फार्म' की खासी चर्चा हुई। दरअसल दर्शकों के मनोरंजन के नाम पर चीन में 'टाइगर फार्म' चलाने का एक इरादा इसकी आड़ में पड़ोसी देशों में मारे गए बाघों की खाल और अंगों का व्यापार चलाना है। विश्व वन्य जीव संगठन (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ) का कहना है कि इन टाइगर फार्मों से ही 'टाइगर वाइन' का कच्चा माल तैयार होता है।

चीन से आये अधिकारियों का कहना था कि उनका देश बाघों के व्यापार से कुछ स्तर तक प्रतिबंध हटायेगा। दूसरी ओर नेपाल एवं बांग्लादेश के विशेषज्ञों ने अपने देशों में बाघों की कम होती संख्या को देखते हुए प्रतिबंध बनाये रखने की मांग उठायी।

तिब्बती किशोर की 1,000 किलोमीटर पैदल यात्रा

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश (एएनआई)। चीनी दमन से बचने के लिये तिब्बत के एक किशोर ने तिब्बत से नेपाल तक की 1,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय की। 15 साल का यह किशोर जमयांग सामतेन अपने दूसरे प्रयास में तिब्बत–नेपाल सीमा को पार करने में सफल रहा।

जमयांग ने बताया है कि उसने अपने समूह के दो सदस्यों की हत्या होते देखी जब पहले प्रयास में वे सीमा पार करने की कोशिश में थे। उसने बताया, ''पहली बार जब ताकला में गिरफ्तार किया गया तब सीमा पुलिस ने हमारे सिर पर बंदूक तानते हुए हमें मारने की धमकी दी। हमें शिपूता ले जाया गया और हमसे उन लोगों की जानकारी मांगी गई जो हमें सड़क तक लेकर आये। पुलिस ने गाइड एवं हमारा मार्ग निर्देशन करने वालों का ब्यौरा भी मांगा तथा कहा कि अगली बार पकड़े जाने पर मारे जाओगे।''

दूसरे प्रयास में वह उसी दल में था जिसपर गत वर्ष सितंबर में नांग्पा–ला में चीनी सेना ने गोली चलाई थी। जमयांग ने धर्मशाला पहुंचने के बाद बताया कि चीनी सीमा सैनिकों की गोलीबारी के बाद उनका समूह दो दलों में विभाजित हो गया। इस समूह के 73 लोगों में से 41 ही भारत पहुंचने में सफल रहे।

इस समूह में भिक्षु, भिक्षुणियां, बच्चे और युवा भी थे। तीस सितंबर को चीनी सैनिकों ने 18,753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नांग्पा–ला दर्रे पर इस समूह पर गोलियां चलाईं जिसमें भिक्षुणी केलसांग नोरत्सो (17) की मौत हो गई।

इस क्षेत्र में मौजूद यूरोपीय पर्वतारोहियों ने इस घटनाक्रम का फिल्मांकन कैमरे में कर लिया था और इसे इंटरनेट पर जारी कर दिया था। इसके अलावा गोलीबारी की घटना को रोमानियाई प्रो टीवी ने भी प्रसारित किया। इस फिल्म में एक चीनी सैनिक को तिब्बतियों के एक समूह पर गोली चलाते हुए स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।

हर साल चीनी अत्याचारों से बचने के लिए तिब्बत से 2500 से 3500 के बीच तिब्बती नागरिक चोरी छिपे भागकर नेपाल आते हैं। वहां से वे भारत और दूसरे देशों में जाकर शरण लेते हैं।